PM → राजीव गांधी ← PVK राव समिति 1985 (कार्ड समिति)

- गाँव के विकास के लिए "ग्रामिण विकास कार्यक्रम" का गठन हो
- जिला के विकास के लिए जिला विकास परिषद होगा।
- पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- वित्तिय व्यवस्था के लिए राज्य वित्त आयोग होना चाहिए।

✓ L.M. सिंघवी समिति ; 1986 → PM → राजीव गांधी

→ पहला राज्य – MP

↳ पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाय।

↳ पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

↳ SC/ST को परिसिमन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान।

↳ महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

↳ बिहार मे → 50% HP - 50% झारखण्ड - 50%

↳ OBC का आरक्षण राज्य के विधान मण्डल द्वारा तय किया जायेगा।

जनसंख्या के अनुपात मे सिटों का विभाजन.

↳ पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन और वित्त आयोग होगा।

पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा

पंचायती राज दिवस

अनु॰ 243 क → 243 ण

243 त - 243 य घ

Z d

प्रधानमंत्री नरसिंह राव

73 वाँ CAA 1992
त्रीस्तरिय पंचायती राज व्यवस्था
24 April 1993
कार्य — 29 विषय
11वी अनुसूची

74 वा CAA 1993
नगरिय पंचायती राज व्यवस्था।
1 जून 1993 लागू
कार्य - 18 विषय
12वी अनुसूची

P. K. थुंगन समिति, 1988.

↳ संवैधानिक आधार पर लाए पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन

↳ हिस्टरिय पंचायती राज व्यवस्था का आधार होना चाहिए

↳ आरक्षण उचित है।

↳ वित्त आयोग के स्थापना.

Note:- कांग्रेस के द्वारा पंचायत मे सुधार करने के लिए सभी समितियों की सिफारिश की समिक्षा के लिए. गाडगिल समिति का गठन किया

* पंचायती राज व्यवस्था से सम्बन्धित समिति :

N.V. गॉडगिल समिति → सविधान समिति

P.K. थुंगन समिति 1988

↳

↳ बलवंतराय मेहता समिति, 1957 – त्रिस्तरीय पंचायती राज

↳ अशोक मेहता समिति, 1977 — द्विस्तरीय पंचायती

↳ G.V.K राव समिति, 1985 — कार्ड समिति

↳ L.M सिंघवी समिति - 1986 — संवैधानिक दर्जा

↳ संथानम समिति, 1962 = पंचायत मे भ्रष्टाचार रोकने लिए

↳ सादिक अली समिति, 1964 → राजस्थान के पंचायत मे सुधार

SC → समाज मे रहते हुए, उपेक्षित है।
ST → समाज से बाहर रहते हुए उपेक्षित)

पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण अनु०

अनु० 243-A :- ग्राम सभा का गठन :-

↳ निर्वाचन सूची मे शामील व्यक्तियों का समूह ग्राम सभा का गठन करेगा।

↳ ग्राम सभा की घोषणा राज्यपाल के पूर्व अनुमति पर विधान सभा द्वारा किया जायेगा